अधिक आयात शुल्क से नहीं आएगी चीनी में मिठास

उज्ज्वल जौहरी
नई दिल्ली, 1 मई

> चीनी उद्योग के पास 30 सितंबर, 2015 को खत्म हो रहे इस चालू चीनी वर्ष तक 2.7 करोड़ टन चीनी होगी जबकि अनुमानित मांग 2.48 करोड़ टन की है।

देसी बाजार में चीनी की गिरती कीमतों को थामने के लिए आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के सरकार के फैसले से तुरंत ही इस क्षेत्र को लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद के ही मुताबिक चीनी कंपनियों के शेयर चढ़ने के बाद गिर गए। 30 अप्रैल को बलरामपुर चीनी 52 हफ्ते के निचले स्तर तक गिरकर 45.30 रुपये के स्तर पर आ गई जबकि श्रीरेणुका शुगर्स और बजाज हिंदुस्तान के शेयर भी गिरावट के साथ कारोबार करते रहे।

भारतीय चीनी मिल संघ के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि हालांकि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे लंबी अवधि में फायदा होगा जब भारत में चीनी की कीमतों में इजाफा होगा। फिलहाल देश में चीनी की कीमतों का ढांचा ऐसा होगा कि इसे आयात बमुश्किल ही कोई खतरा होगा लेकिन अधिक शुल्क होने से आयात पर रोक लगाने में तभी मदद मिलेगी जब कीमतें तेज हों। भविष्य में ऐसा होने की उम्मीद कम ही है।

खासबात यह है कि बड़े मसलों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह क्षेत्र अत्यधिक आपूर्ति की वजह से लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहा है। उद्योग के पास 30 सितंबर, 2015 को खत्म हो रहे इस चीनी वर्ष तक 2.7 करोड़ टन चीनी होगी जबकि अनुमानित मांग 2.48 करोड़ टन की है। इसलिए चीनी अधिशेष 95 लाख टन बढ़ जाएगा जिसके 60 लाख टन तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्मा के मुताबिक गिरती कीमतों को रोकने का एक मात्र तरीका यह है कि सरकार को चीनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए।

दूसरी तरफ लागत बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख चीनी कंपनियां बलरामपुर चीनी और बजाज हिंदुस्तान के मुनाफे पर और भी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासित मूल्य को जस का तस बना रखा है।

Business Standard
2/5/15

...ying capacity. However, the export subsidy is a short term relief. For the